

सीपीईसी (CPEC) का दूसरा चरण

प्रलम्बिस् के लयि:

चीन-पाकसि्तान आर्थकि गलयिरा, बेल्ट एंड रोड इनशिऐटिवि, ग्वादर पोर्ट, पाकसि्तान अधकिृत कश्मीर, स्ट्रगिस् ऑफ पर्ल्स, पनामा नहर, एलओसी ।

मेन्स के लयि:

भारत के हतिं पर देशों की नीतयिं और राजनीतकिा प्रभाव, भारत को शामिल और/या इसके हतिं को प्रभावति करने वाले समूह और समझौते, सीपीईसी और इसका प्रभाव ।

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में पाकसि्तान ने 60 बलियिन अमेरकिी डॉलर के [चीन-पाकसि्तान आर्थकि गलयिरा \(CPEC\)](#) के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर कयि है ।

- इससे पहले अरबों डॉलर के [चीन-पाकसि्तान आर्थकि गलयिरा \(CPEC\)](#) बुनयिदी ढांचा परयिोजना में शामिल होने को लेकर पाकसि्तान ने [तालबिन के नेतृत्व वाले अफगानसि्तान](#) के साथ चर्चा की थी ।
- दूसरा चरण मुख्य रूप से [वशिष आर्थकि क्षेत्रों \(SEZs\)](#) के वकिस और औद्योगिकरण के इर्द-गर्द घूमता है ।

चीन-पाकसि्तान आर्थकि गलयिरा:

- CPEC चीन के उत्तर-पश्चिमी झजियिांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र और पाकसि्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचसि्तान में ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली बुनयिदी ढांचा परयिोजनाओं का 3,000 किलोमीटर लंबा मार्ग है ।
- यह [पाकसि्तान और चीन के बीच एक द्वपिक्षीय परयिोजना](#) है, जसिका उद्देश्य ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनयिदी ढांचा वकिस परयिोजनाओं के साथ राजमार्गों, रेलवे एवं पाइपलाइन्स के नेटवर्क द्वारा पूरे पाकसि्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है ।
- यह चीन के लयि ग्वादर बंदरगाह से मध्य पूरव और अफ्रीका तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करेगा ताकि चीन हदि महासागर तक पहुँच प्राप्त कर सके तथा चीन बदले में पाकसि्तान के ऊर्जा संकट को दूर करने और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लयि पाकसि्तान में वकिस परयिोजनाओं का समर्थन करेगा ।
- CPEC, [बेल्ट एंड रोड इनशिऐटिवि \(BRI\)](#) का एक हसिसा है । वर्ष 2013 में शुरू कयि गए 'बेल्ट एंड रोड इनशिऐटिवि' का उद्देश्य दक्षिण-पूरव एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि एवं समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है ।

CPEC पर भारत का रुख:

- CPEC को लेकर भारत ने चीन के समकष वशिष जताया है क्योँकि पाकसि्तान का कब्जा वाला कश्मीर (PoK) क्षेत्र भी इसके तहत आता है ।
- भारत, [क़्वाड \(भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान\)](#) का सदस्य है जो बुनयिदी ढाँचे हेतु देशों को यथार्थवादी वकिल्प प्रदान कर सकता है एवं चीनी प्रतकिरयिा के लयि उपयुक्त हो सकता है ।
 - उदाहरण के लयि: [ब्लू डॉट नेटवर्क \(BDN\)](#) और [बलिड बैंक बेटर वर्ल्ड \(B3W\) पहल](#) ।

भारत के लयि CPEC के नहितार्थ:

- **भारत की संप्रभुता:** भारत CPEC की लगातार आलोचना करता रहा है, क्योँकि यह पाकसि्तान अधकिृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जो भारत और पाकसि्तान के बीच एक वविदति क्षेत्र है ।
- कॉरडोर को भारत की सीमा पर स्थति कश्मीर घाटी के लयि वैकल्पकि आर्थकि सड़क संपर्क के रूप में भी माना जाता है ।
- **नयितरण रेखा (एलओसी)** के दोनों ओर कश्मीर को 'वशिष आर्थकि क्षेत्र' घोषति करने के लयि स्थानीय व्यापारयिं और राजनीतजिजों द्वारा आह्वान कयिा गया है ।

- अगर गलित-बाल्टसितान औद्योगिक विकास के साथ वदिशी नविश को आकर्षित करता है, तो CPEC के सफल होने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पाकसितानी क्षेत्र के रूप में इस क्षेत्र की धारणा को और मज़बूती मिलेगी, जिससे 73,000 वर्ग कर्मी. भूमि पर भारत का दावा कमज़ोर हो जाएगा जो कर्मी 1.8 मिलियन से अधिक लोगों का घर है।
- **समुद्र के माध्यम से व्यापार पर चीनी नयितरण:** पूर्वी तट पर प्रमुख अमेरिकी बंदरगाह चीन के साथ व्यापार करने के लिये पनामा नहर पर निर्भर हैं।
 - एक बार CPEC का कार्य पूरा हो जाने के बाद चीन अधिकांश उत्तरी व लैटिन अमेरिकी उद्यमों के लिये एक 'छोटा और अधिक कफायती' व्यापार मार्ग की पेशकश करने की स्थिति में होगा।
 - यह चीन को उन शर्तों को नरिधारित करने की शक्ति देगा जिनके द्वारा अटलांटिक एवं प्रशांत महासागरों के बीच माल की अंतरराष्ट्रीय आवाज़ाही होगी।
- **चीन की 'सट्रगि ऑफ प्रल्स' नीति:** चीन अपनी महत्त्वाकांक्षा के साथ हृदि महासागर में उपस्थिति बिद्धा रहा है; यह अमेरिका द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है और अक्सर भारतीय रक्षा विश्लेषकों द्वारा हवाई क्षेत्रों व बंदरगाहों के नेटवर्क के माध्यम से भारत को घेरने की चीनी रणनीतिको संदर्भित करने के लिये इस्तेमाल किया जाता है।
 - चटगाँव बंदरगाह (बांग्लादेश), हंबनटोटा बंदरगाह (श्रीलंका), पोर्ट सूडान (सूडान), मालदीव, सोमालिया और सेशेल्स में मौजूदा उपस्थितिके साथ कम्युनसिट राष्ट्र (चीन) द्वारा ग्वादर बंदरगाह पर नयितरण के माध्यम से हृदि महासागर पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करना है।
- **आउटसोर्सिंग गंतव्य के रूप में पाकसितान का उदय:** यह पाकसितान की आर्थिक प्रगति को गति देने हेतु तैयार है।
 - मुख्य रूप से कपड़ा और नरिमाण सामग्री उद्योग में भारत व पाकसितान की दोनों देशों के शीर्ष तीन व्यापारिक भागीदारों में से दो देश अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात में सीधी प्रतसिपर्द्धा है।
 - मुख्य रूप से भारतीय नरियात चीन से कच्चे माल की सुलभ आपूर्तिके साथ पाकसितान को इन क्षेत्रों में एक प्रतसिपर्द्धी क्षेत्रीय बाज़ार बनने हेतु उपयुक्त परस्थितियाँ उपलब्ध होंगी।
- **BR1 द्वारा मज़बूत व्यापार और चीन का प्रभुत्व:** चीन की बीआरआई परियोजना जो बंदरगाहों, सड़कों और रेलवे के नेटवर्क के माध्यम से चीन और शेष यूरेशिया के बीच व्यापार संपर्क पर केंद्रित है, को अक्सर इस क्षेत्र में राजनीतिक रूप से हावी होने की चीन की योजना के रूप में देखा जाता है। CPEC इसी दिशा में एक और बड़ा कदम है।
 - चीन जो कर्मी बाकी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं द्वारा समर्थित और अधिक एकीकृत है, **संयुक्त राष्ट्र** एवं अलग-अलग राष्ट्रों के साथ बेहतर स्थिति में होगा, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट हासिल करने की योजना को प्रभावित कर सकता है।

आगे की राह:

- CPEC पर भारत की भवषिय की रणनीति BR1 परियोजना के संभावित लाभों के साथ-साथ नुकसान के सावधानीपूर्वक पुनर्मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिये।
- भारत को अपनी रणनीतिक परियोजनाओं जैसे- **बांग्लादेश, चीन, भारत और म्यांमार आर्थिक गलियारे** (BCIM) और चाबहार बंदरगाह के विकास पर कार्य की गति को तीव्र करना चाहिये।
- एशिया-अफ्रीका ग्रीथ कॉरिडोर भारत-जापान आर्थिक सहयोग समझौता है, यह भारत को महत्त्वपूर्ण रणनीतिक लाभ प्रदान कर चीन को प्रतसितुलित कर सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस